eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

विकसित भारत 2047: विकास की ओर एक पहल– ग्रामीण विकास एवं नगरीकरण की चुनौतियॉ

डॉ0 ममता भारद्वाज[1]
[1]असिस्टेण्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, बी०डी०एम०म्यू० गर्ल्स डिग्री कॉलेज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद

Received: 08 November 2025, Accepted: 20 November 2025, Published online: 30 November 2025

Abstract

भारत 2047 तक अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण करेगा। भारत सरकार ने इस अवसर को अपना लक्ष्य बनाते हुए ''विकसित भारत 2047'' की परिकल्पना को प्रस्तुत किया है। यह केवल आर्थिक समृद्धि का कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकि, पर्यावरणीय और शासन से संबंधित समग्र परिवर्तन का दृष्टिकोण है। भारत की विकास यात्रा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के सशक्तीकरण पर निर्भर करती है। एक ओर जहाँ ग्रामीण भारत को विभिन्न योजनाओं, रोजगार और उत्पादन में तेजी लाकर उसे आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है वहीं शहरीकरण की अनियोजित वृद्धि नई चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही है। इस शोध पत्र में ग्रामीण विकास एवं नगरीकरण की चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए, 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने के मार्ग में आने वाले अवसरों और बाधाओं का विवेचन किया गया है।

सूचक शब्दः– विकसित भारत 2047, ग्रामीण विकास, नगरीकरण, सतत विकास, शहरी नियोजन, स्मार्ट ग्राम, डिजिटल इंडिया।

Introduction

भारत आज विश्व की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत सरकार ने 2047 तक इसे विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प ''अमृत काल'' के रूप में रखा है। विकसित भारत 2047 केवल आर्थिक सूचकांकों में प्रगति का संकेत नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समावेश, तकनीकी नवाचार, पर्यावरणीय संतुलन और सुशासन पर आधारित एक समग्र दृष्टिकोण है।

भारत की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है, जबकि नगरीकरण की दर में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण विकास और शहरीकरण के बीच संतुलन बनाए रखना भारत के विकास पथ का प्रमुख आधार है।

अनुसंधान के उद्देश्य– विकसित भारत 2047 की अवधारणा और नीति ढाँचे को समझना ।

- ग्रामीण विकास से संबंधित प्रमुख योजनाओं, उपलब्धियों और चुनौतियों का अध्ययन करना।
- नगरीकरण की वर्तमान स्थिति एवं उससे उत्पन्न समस्याओं का विश्लेषण करना ।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समन्वित विकास के लिए नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति– यह शोध द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। सरकारी रिपोर्ट, नीति दस्तावेज, भारत सरकार की वेबसाइटें, जनगणना रिपोर्ट और विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों का विश्लेषण किया गया है।

1. **विकसित भारत 2047 की अवधारणाः–** ''विकसित भारत 2047'' का उद्देश्य भारत को सरकार का एक व्यापक विजन है, जिसका लक्ष्य भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है अर्थात वर्ष

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

2017 में जब प्रत्येक भारतवासी आजादी के 100 वें वर्ष में प्रवेश करेगा तब भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। इस विजन में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरण स्थिरता और सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करता है। यह युवाओं, गरीबों महिलाओं और किसानों जैसे मुख्य स्तम्भों पर केन्द्रित है। इसका लक्ष्य समावेशी विकास के माध्यम से समाज के हर वर्ग की समृद्धि सुनिश्चित करना है और भारत को उच्च जीवन स्तर, नवाचार और स्थिरता के साथ एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना है।

''विकसित भारत 2047'' का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर, समावेशी, और वैश्विक नेतृत्वकारी राष्ट्र बनाना है। इस दृष्टि के चार प्रमुख स्तम्भ हैं–

1– समृद्ध भारत – मजबूत अर्थव्यवस्था, तकनीकी प्रगति और रोजगार सृजन ।

2– सशक्त भारत – आधुनिक रक्षा, विज्ञान और नवाचार की दिशा में प्रगति ।

3. समावेशी भारत – सामाजिक न्याय, समान अवसर और लैंगिक समानता ।

4– सतत भारत – पर्यावरणीय संरक्षण और हरित विकास यह दृष्टि केवल GDP वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण जीवन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल पहुँच, शहरी नियोजन, पर्यावरण और संस्कृति जैसे क्षेत्रों को भी शामिल करती है। इसका उद्देश्य 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करना है। समावेशी विकास सुनिश्चित करना और सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और कल्याण को बढ़ावा देना। तेज पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रणाली को बढ़ावा देना, जिसमें भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। युवाओं को विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना और ''विकसित भारत राजदूत – युवा कनेक्ट'' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी आवाज को शामिल करना।

2. ग्रामीण विकास–

2.1. ग्रामीण विकास की आवश्यकता – भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। आज भी लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में ही बसती है अतः एक राष्ट्र तभी शक्तिशाली व समृद्ध हो सकता जब हमारे गाँव गरीबी तथा पिछड़ेपन से मुक्त हो। परन्तु ग्रामीण भारत दीर्घकाल से विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व जनसंख्यात्यक समस्याओं से घिरा है आज प्रत्यक्ष रूप से सामुदायिक विकास योजनाएँ, पंचायतीराज व्यवस्था, प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण,ग्रामीण पुर्निर्माण कार्यक्रम, शिक्षा का प्रसार, लघु उद्योगों को बढावा, सहकारिता आन्दोलन, कृषि का आधुनिकीकरण, विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण की सुविधाएँ और सवैधानिक सुरक्षाएँ आदि ने ग्रामीण समुदाय के लोगों की कार्यविधियाँ, सोचने के तरीकों तथा व्यवहार प्रतिमानों को विशेष रूप से प्रभावित तो किया हैं परन्तु आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में घर गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं सफाई, ऋण–ग्रस्तता, अस्पृश्यता, जातिवाद और कृषि पर निर्भरता जैसी समस्याएँ विद्यमान हैं।

2.2. प्रमुख सरकारी पहलें– स्वतन्त्रता के उपरान्त गाँव के सर्वमुखी विकास पर जोर दिया गया और इस सम्बंध में अनेक कार्यक्रम सरकारी और गैर–सरकारी स्तर पर सम्पन्न किए गए। भारत में ग्रामीण विकास के लिए अनेक प्रयास किए गए। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पूरा करने के लिए आज सरकार ने कई योजनाओं को शुरु किया है जिसमें से कुछ प्रमुख प्रयास निम्नांकित हैं–

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

• **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)** – यह सरकार का एक प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। इसे 25 दिसम्बर, 2000 को ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क रहित बस्तियों को एक ही बारहमासी सड़क के जरिये पूरे साल सड़क संपर्क देने के मकसद से शुरू किया गया था, ताकि ग्रामीण आबादी की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। चालू वित्त वर्ष 2025–26 के लिए, 19,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में सुधार, बारहमासी सड़क संपर्क सुनिश्चित करने और गाँवों में आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिये निरन्तर मदद को दर्शाता है।

• **मनरेगा योजना–(MGNREGA)**–''महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम'' एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य कार्य करने का अधिकार है जिससे अकुशल श्रमिकों के परिवारों को एक वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार मिल सके। उनको अपने गाँवों में ही रोजगार प्राप्त हो जाये और उनकी बेरोजगारी एवं इससे उत्पन्न गरीबी को समाप्त किया जा सके।

इस कानून को सरकार द्वारा ''दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्यक्रम'' कहा जाता है। विकास रिपोर्ट 2014, विश्व बैंक ने इसे ''ग्रामीण विकास का तारकीय उदाहरण'' कहा। मनरेगा का एक और उद्देश्य है टिकाऊ संपतियों का निर्माण करें। आवेदक के निवास के 5 किमी के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है, और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना है। यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं किया गया है, तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता के हकदार हैं। इस प्रकार, मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी हकदार है। इस योजना से अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों को लाभ प्राप्त हो रहा है।।

• **प्रधानमंत्री आवास योजना (GRAMIN)** – (पीएमएवाईजी) प्रधानमंत्री ने 20 नवम्बर, 2016 को 2022 तक 2 करोड़ 95 लाख घर बनाने के लक्ष्य के साथ इसका शुभारंभ किया था। भारत में ग्रामीण गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिये भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक प्रमुख सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार को पक्का मकान प्रदान करना है।

• **स्वच्छ भारत मिशन (GRAMIN)** :– भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरुआत की गयी, जो एक प्रमुख राष्ट्रीय अभियान है। इसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ, स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना है। जिसके लिए सरकार द्वारा समय–समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने और स्वच्छता के प्रति जागरुकता फैलाने के लिये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इसमें स्कूलों, पंचायतों और स्थानीय संगठनों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता हैं। स्वच्छ शौचालय निर्माण हेतु प्रत्येक पात्र परिवार को वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।

• **डिजिटल ग्राम योजना एवं भारत नेट–** भारत नेट परियोजना का उद्देश्य देश भर में प्रत्येक ग्रामपंचायत (GP) को हाई–स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। यह विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में से एक है, जो किफायती ब्रॉडबैंड पहुँच प्रदान करने तथा ग्रामीण भारत में ई–स्वास्थ्य, ई–शिक्षा और ई–गवर्नेंस जैसी विभिन्न सेवाएँ शुरु करने में सक्षम बनाती है। वर्ष 2025 तक, भारतनेट परियोजना के अन्तर्गत लगभग 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को सेवा के लिये तैयार किया जा चुका है।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

• **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA)** का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों में डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करना है मार्च 2024 तक 6.39 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। **राष्ट्रीय ब्रांडबैंड मिशन (NBM)** डिजिटल बुनियादी ढाँचे में तेजी लाने के लिये जनवरी 2025 में लॉन्च किया, इसमें **(NBM)** 2.0 शामिल है। मोबाइल कनेक्टिविटी 6.18 लाख गाँवों में 4G कवरेज के साथ दिसम्बर 2024 तक लगभग 6.25 लाख गाँव मोबाइल से युक्त थे।

• **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)**– यह भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। यह योजना स्व–रोजगार को बढ़ावा देने और ग्रामीण गरीबों को संगठित करने पर केन्द्रित है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना और उन्हें स्व–रोजगार के लिये सक्षम बनाना है। यह कार्यक्रम 2011 में 5.1 बिलियन के बजट के साथ शुरु किया गया था। इस कार्यक्रम को विश्व बैंक द्वारा 1 बिलियन डॉलर के ऋण के साथ समर्थन भी प्राप्त है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को कम करना और उनके लिये स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है।

2.3. ग्रामीण विकास की चुनौतियाँ –

1– कृषि संकट– कृषि सम्पूर्ण देश की प्रगति की नींव और रीढ़ है। इसीलिये स्वतंत्रता के पश्चात सरकार का ध्यान ग्रामीण – आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की तरफ गया। आज हम खाद्यान्न में केवल आत्मनिर्भर ही नहीं है बल्कि अनेक देशों को खाद्यान्न निर्यात भी करते हैं परन्तु इतना होते हुए भी अभी ग्रामीण – आर्थिक ढाँचा इतना शक्तिशाली नहीं बन पाया है। क्योंकि समय–समय पर कृषि पर उत्पादन की लागत बढ़ने से, बाजार में अस्थिरता होने से एवं जलवायु परिवर्तन होने से उस पर संकट मंडराता रहता है।

2. शिक्षा एवं कौशल विकास की कमी – कहने को तो ग्रामीण शिक्षा के प्रचार–प्रसार की ढेरों योजनाएँ चल रही हैं तथा कागजों पर हमने साक्षरता की डर बढ़ा भी ली है, परन्तु सच तो यह है कि ग्रामीण अंचलों में शिक्षा के प्रचार–प्रसार के जितने दावे किये जा रहे है, परिणाम उससे काफी कम प्राप्त हुए हैं। आज भी हम लक्ष्य से बहुत दूर हैं। आज शिक्षा के साथ–साथ कौशल विकास की भी काफी कमी है जिसकी हलय हमारे सामने मुँह फाड़े खड़ी हुई है।

3. स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता:– स्वास्थ्य ढाँचे की कमी, विशेषज्ञों की कमी, परिवहन और सड़क सुविधाओं का अभाव, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव, तकनीकी व डिजिटल गैप प्रशासनिक व प्रबंधन जैसी कई समस्याओं से ग्रामीण जनता जूझती है जिसका निदान होना आवश्यक है।

4. ग्रामीण पलायन एवं बेरोजगारी:– कृषि में कम उत्पादन और आय अस्थिरता, रोजगार के सीमित अवसर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, सूखा, बाढ़, जल संकट, विकास योजनाओं का ग्राम स्तर पर अनुपलब्ध होना, सड़कों, बिजली, पेयजल तथा बेहतर जीवन स्तर की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं।

5. तकनीकी संसाधनों तक सीमित पहुँच:– कई गाँवों में अब भी हाई–स्पीड इंटरनेट, ब्रांडबैड और स्थिर मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नही हैं। बिजली की अनियमित या सीमित आपूर्ति तकनीकी संसाधनों के उपयोग को बाधित करती है। ग्रामीण लोग डिजिटल तकनीक का उपयोग करने का सही कौशल नही रखते हैं।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

2.4 समाधान की दिशा में प्रयासः– ग्रामीण विकास तभी संभव है जब इन समस्याओं का निदान हो स्वास्थ्य सेवाओं से सबंधित स्थास्थ्य ढाँचे का विस्तार, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता, तकनीकी नवाचारों का उपयोग और समुदाय की भागीदारी इस समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। कृषि में स्मार्ट टेक्नोलॉजी, जैविकखेती, बेहतर कृषि मूल्य, कृषि पर आधारित उद्योग, ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और पर्यटन को बढावा, ग्रामीण MSME क्लस्टर, डिजिटल उद्यमिता कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना, रोजगार गांरटी योजनाऐं ग्रामीण पर्यटन एवं शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण की तरफ प्रयास करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रो में ब्रांडबैंड और 4G/5G नेटवर्क का विस्तार डिजिटल साक्षरता मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण। स्कूलों और पंचायत भवनों में कम्प्यूटर लैब व फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराना।

3. नगरीकरण और उसकी चुनौतियाँ–

1. शहरीकरण की स्थिति – भारत में 1951 में शहरी जनसंख्या लगभग 17 प्रतिशत थी, जो 2021 तक 36 प्रतिशत तक पहुँच गई है। 2047 तक इसे 50 प्रतिशत तक पहुँच जाने की संभावना मानी जा रही हैं। भारत में जिस तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ी है, उस गति से यहाँ नगरीय विकास नहीं हो पाया है। पिछले कुछ वर्षों में नगरीय जनसंख्या की बढ़ोतरी के अनुपात में नगरों में वे सब आवश्यक सुविधाएं हम नहीं जुटा पाये हैं जो अच्छे नगरीय जीवन के लिए अनिवार्य है।

2. प्रमुख योजनाएँ – नगरीय विकास की दृष्टि से देश में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ चलाई गई उनमें से कुछ निम्नलिखित हैः–

- **स्मार्ट सिटी मिशन (2015):**– स्मार्ट सिटी मिशन 2015 का उद्देश्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत के शहरों को अधिक नागरिक–अनुकूल, टिकाऊ और जीवन की बेहतर गुणवत्ता वाले बनाना है। इसके तहत शहरों में मुख्य अवसंरचना का विकास, कुशल शहरी गतिशीलता, सुनिश्चित जलापूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन और ई–गवर्नेस जैसे स्मार्ट समाधान लागू किये जाते हैं
- **अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT)** – यह भारत सरकार की एक शहरी विकास योजना है, जिसका उद्देश्य देश के शहरों और कस्बों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना है। यह 25 जून 2015 को शुरु की गई थी इसका मुख्य ध्यान पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, वर्षाजल निकासी और पार्कों जैसे क्षेत्रों पर है।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना (Urban)-** शहरी (पीएमएवाईयू) (19) भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एम ओ एच यू ए) डारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसे 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। जिसका उद्देश्य शहरों में सभी योग्य परिवारों को किफायती पक्का घर उपलब्ध कराना है। यह मुख्यरूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग के परिवारों को लाभ प्रदान करती हैं।
- **स्वच्छ भारत मिशन (Urban)**– यह भारत सरकार की एक प्रमुख राष्ट्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, खुले में शौच–मुक्त (ओडीएफ) स्थिति और स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करना है। इसे 2 अम्टूबर 2014 को महात्मा गाँधी जी की जयन्ती पर लॉन्च किया गया था।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

3. शहरीकरण की चुनौतियाँ – शहरीकरण एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन इसके साथ अनेक सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और प्रशासनिक चुनौतियाँ जुड़ी होती हैं जिसमें से प्रमुख चुनौतियाँ निम्न है–

1. अनियोजित विस्तार– सड़कें, जलापूर्ति, सीवरेज, बिजली परिवहन आदि पर अनियन्त्रित बोझ बढ़ जाता है। यातायात जाम, परिवहन अव्यवस्था, झुग्गी झोपड़ियों का बढ़ना, पर्यावरणीय क्षरण, प्रशासनिक नियंत्रण की कमी आदि शहरों के टिकाऊ विकास को गंभीर रूप से बाधित करता है।

2. **बुनियादी सुविधाओं की कमी–** असंतुलित शहरी वृद्धि के कारण बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में गंभीर कमी देखने को मिलती है। जैसे स्वच्छ पेयजल की कमी, स्वच्छता एवं सीवरेज समस्याएँ, आवास की समस्या, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, परिवहन एवं यातायात अव्यवस्था, कचरा प्रबंधन की कमी, शिक्षा सुविधाओं की कमी आदि ।

3. **पर्यावरण प्रदूषण–** वाहनों की संख्या, उद्योगों का धुआँ, महानगरों में हवा की गुणवत्ता, सीवेज के उचित निस्तारण न होना, कचरा संग्रह और निस्तारण की कमी से कूड़े के ढेर लगना, प्लास्टिक और ई–वेस्ट का प्रबंधन बड़ी चुनौती बन गया है।

4 **शहरी गरीबी और असमानता** – शहरों में एक तरफ उच्चस्तरीय मॉल और गगनचुम्बी इमारतें हैं, वहीं इसरी तरफ झुग्गियाँ और गंदगी से भरे इलाके हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और अवसरों में काफी अंतर रहता है। शहरों में अमीर और गरीब के बीच भारी अंतर दिखाई देता है।

5. **स्मार्ट सिटी में डिजिटल विभाजन** – स्मार्ट सिटी का मूल लक्ष्य तकनीक आधारित, कुशल, पारदर्शी और समावेशी शहरी प्रबंधन प्रणाली विकसित करता है। परंतु वास्तविकता यह है कि शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ डिजिटल विभाजन के एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर रहा हैं क्योंकि तकनीक आधारित सेवाओं का लाभ केवल कुछ सीमित समूहों तक ही पहुँच पाता है।

3.4 समाधान और नीति सुझाव –

- **संतुलित नगरीकरण नीतिः–** बड़े महानगरों पर जनसंख्या, रोजगार और संसाधनों का अत्यधिक केंद्रीकरण शहरी समस्याओं का मुख्य कारण है इसके लिये छोटे और मध्यम शहरों का विकास करके एक बहु–केन्द्रीय शहरी नेटवर्क तैयार किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और डिजिट ल कनेक्टिविटी बेहतर की जाए जिससे शहरों की ओर पलायन कम होगा।
- **ग्रीन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर–** शहरों की मास्टर प्लानिंग में ग्रीन जोन, ब्लू–ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, साइकिल ट्रैक, सार्वजनिक परिवहन को अनिवार्य बनाया जाये। जिससे शहर अधिक रहने योग्य और पर्यावरणीय रूप से संतुलित बनेंगे।
- **सस्ती आवास नीति–** सस्ती आवास योजनाएँ, किराया आवास मॉडल, मिश्रित आवास नीति लागू की जाए जिससे झुग्गीकरण कम होगा और सभी वर्गों को सुरक्षित आवास मिलेगा।
- **डिजिटल शहरी शासन** – सभी शहरी सेवाओं का डिजिटलीकरण, एकीकृत शहरी पोर्टल, स्मार्ट सिटी तकनीकी का उपयोग, मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत प्रबंधन डिजिटल भुगतान और वित्तीय प्रबंधन में सुधार, शहरी सेवाओं में डेटा–आधारित निर्णय, साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण PPP मॉइल के माध्यम से डिजिटल परियोजनाएँ, दूरस्थ निगरानी और नियन्त्रण केन्द्र स्मार्ट सामाजिक सेवाएँ प्रदान करना।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

• **एकीकृत ग्रामीण–शहरी नीति (RURBAN मिशन):–** जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन न हो इसके लिये ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अवसर बढ़ाना, छोटे और मध्यम कस्बों को विकास के केन्द्र बनाना, स्मार्ट और सतत शहरी विकास, सामाजिक सेवाओं का समान वितरण, हरित एवं जलवायु संवेदनशील शहरी–ग्रामीण नीति को अपनाने का प्रयास करना चाहिए

4. ग्रामीण और शहरी विकास का समन्वयः– भारत का विकास तभी संभव है जब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र एक दूसरे के पूरक बने। RURBAN मिशन इस दिशा में कार्य कर रहा है, जो ग्रामीण इलाकों में शहरी सुविधाएँ पहुँचाने का प्रयास है। साथ ही क्लस्टर आधारित औद्योगीकरण, डिजिटल ग्रामीण हब, और ग्रामीण शहरी आपूर्ति श्रंखला के माध्यम से परस्पर निर्भरता बढ़ाई जा सकती है।

5. सतत विकास और भविष्य की रणनीति – इसके लिये बहु–आयामी और दीर्घकालिक कदमों की आवश्यकता होती हैंः–

1. हरित ऊर्जा और पर्यावरण संतुलन – ''विकसित भारत 2047'' का लक्ष्य पाने के लिये सरकार को उन्नत सोलर पैनल, हरित हाइड्रोजन उत्पान, पर्यावरण– अनुकूल भवन कोड, हरित परिवहन, जनभागीदारी और जागरुकता, ग्रीन इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन के लिए अधिक जोर देने की आवश्यकता है।

2. शिक्षा एवं कौशल विकास – शिक्षा और कौशल विकास सतत शहरी विकास की रीढ़ है इसके लिए इंडस्ट्री – एकैडेमिया साझेदारी, ग्रीन स्किल और ब्लू इकोनोमी शिक्षा, माइको–क्रेडेंशियल और नैनो डिग्री सिस्टम, स्मार्ट सिटी, डिजिटलीकरण का समान वितरण आदि पर ध्यान देना जरुरी हैं।

3– महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता– आर्थिक विकास को बढ़ावा, सामाजिक स्थिरता, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए कदम, भेदभावपूर्ण कानूनों में बदलाव, आर्थिक और हानिकारक प्रथाओं का उन्मूलन, सशक्तिकरण और नेतृत्व को बढ़ावा देना, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करके ऐसा भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है जो लैंगिक समानता पर आधारित हो।

4. डिजिटल इंडिया और AI – आधारित शासन – डिजिटल इंडिया का लक्ष्य भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाना। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में 5 जी के विस्तार जैसी पहलों के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार, डिजिटल सेवाएँ जैसे डिजीलॉकर, उमंग ऐप और प्लेटफार्म के माध्यम से नागरिक सेवाओं तक पहुँच को आसान बनाना डिजिटल समावेशन से निरक्षरता जैसे मुद्दों का समाधान किया जाता है।

सभागार पंचायत राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया AI टूल, जो ग्राम सभाओं की बैठकों का सांराश तैयार करता है डेटा एनालिटिक्स निर्णय लेने के प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिय डेटा का उपयोग करना। AI आधारित शासन डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को प्राप्त कर शासन को अधिक कुशल और नागरिकों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाता है।

5. **स्थानीय नवाचार को प्रोत्साहन–** स्थानीय नवाचार को बढ़ावा देने के लिये सरकार और अन्य संस्थाएँ विभिन्न उपाय कर रही है, जैसे– वित्तीय सहायता, क्षेत्रीय क्लस्टर बनाना अनुसंधान और विकास (R&D) को प्रोतसाहन देना और शिक्षा व कौशल विकास पर ध्यान केन्द्रित करना। स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों और अटल टिंकरिग लैब्स के माध्यम से छोटे शहरों को नवाचार के लिये प्रोत्सहित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

निष्कर्ष– विकसित भारत 2047 की अवधारणा तभी साकार हो सकती है जब ग्रामीण सशक्तिकरण और शहरी संतुलन दोनों साथ–साथ चलें। जहाँ एक ओर गाँवों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, बिजली तकनीकी संसाधनों का व्यवस्था, रोजगार के साधन आदि की आवश्यकता पर बल देना जरूरी है वही दूसरी ओर शहरों में सतत शहरी नियोजन. पर्यावरण संतुलन, स्वच्छता, रोजगार तथा समावेशी विकास की आवश्यकता है।

भारत की वास्तविक शक्ति उसकी विविधता और सामूहिकता में निहित है। ''विकसित भारत 2047'' केवल सरकार का ही नहीं बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक का मिशन है– ''सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास'' के सिद्धान्त पर आधारित

सन्दर्भ ग्रंथ सूचीः–

1. गुप्ता, प्रो0 एम0एल0 एवं शर्मा, डॉ0डी0डी0 **ग्रामीण तथा नगरीय समाजशास्त्र** साहित्य भवन पब्लिकेशन्सः आगरा, पृष्ठ संख्या– 229,239,246

2. चौबे, विवेक **भारतीय गाँवों पर नगरीकरण का प्रभाव,** वाई0के0पब्लिशर्स, आगरा पृष्ठ संख्या – 03

3. द्विवेदी, सुश्री उपमा रूवाली, डॉ0 प्रिंयका एनं **''मनरेगा योजना का अनुसूचित जाति के श्रमिकों पर प्रभावः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन''** राधा कमल मुखर्जी, चिन्तन परम्परा, वर्ष 26 अंक 1, जनवरी–जून, 2024 समाज विज्ञान विकास संस्थान, बरेली (उ0प्र0) पृष्ठ संख्या – 116

4. लवानिया, डॉ0एम0एम0, **ग्रामीण समाजशास्त्र,** जैन, शशी के0 रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृष्ठ सख्या – 251,305

5. वर्मा, सबलिया बिहारी, पाण्डेय, आभनारायण जालोदा, शिवकुमार, **ग्रामीण विकास,** आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर 302003 (राजस्थान) पृष्ठ संख्या – 294

6. सिंह, डॉ0वी0एन0 सिंह, डा0 जनमेजय **ग्रामीण समाजशास्त्र** विवेक प्रकाशन जवाहर नगर, दिल्ली – 7 पृष्ठ संख्या – 149

7. सिंह, डॉ0 विमलेश **''विकसित भारत @ 2047 लक्ष्य प्राप्ति में एक प्रगतिशील एवं समावेशी शिक्षा प्रणाली के अनिवार्यता''** अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान– शोध पत्रिका, वॉल्यूम –13 (जनवरी–मार्च, 2025) पृष्ठ संख्या – 57

8. नीति आयोग (2023) विकसित भारत 2047: Vision Document. भारत सरकार

9. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार वार्षिक रिपोर्ट–2023–24

10. इण्टरनेटः–

https:// www.pib.gov.in
https://www.nrega.nic.in
https://www.dord.gov.in
https://sbmgub.in SBMGRAMEEN
https://www.drishtiias.com